जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Shelter for all in Rural Areas

856. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether any scheme has been launched by Government to provide shelter for all, particularly in the rural areas;

(b) if so, the steps taken in that direction by different States during last five years; and

(c) the details of rural housing schemes launched by Government in every State during last five years?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS & EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): (a) Indira Awaas Yojana which is a centrally sponsored scheme is being implemented all over the country with the objective to provide assistance for construction of houses to members of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes, freed bonded labourers and also to non-SC/ST rural poor below the poverty line in rural areas.

(b) and (c) A Statement showing the number of houses constructed under Indira Awaas Yojana for the various State/UTs during the last five years is annexed.

Statement

Number of houses constructed under Indira Awaas Yojana for various States/UTs during 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97 and 1997-98

Houses constructed *(in Nos.)*

Name of the State	1993-94 Achievement	1994-95 Achievement	1995-96 Achievement	1996-97 Achievement	1997-98* Achievement
Andhra Pradesh	44897	57483	69086	46181	88311
Arunachal Pradesh	120	219	420	387	291
Assam	4304	6862	24871	13401	10570
Bihar	88960	59216	114506	133244	85740
Goa	358	329	967	466	512
Gujarat	7117	7895	31770	30481	17854
Haryana	1552	3536	9024	6153	3042
Himachal Pradesh	629	853	1727	2373	1843
Jammu & Kashmir	390	1697	3554	10197	4306
Karnataka	8820	13831	37460	45503	43522
Kerala	16999	18549	29368	23202	12834
Madhya Pradesh	48108	48967	125757	87371	65604
Maharashtra	18870	22812	66648	58244	60709
Manipur	208	197	784	715	1096
Meghalaya	353	283	207	646	305
Mizoram	240	368	569	369	302
Nagaland	1536	895	470	3691	1933
Orissa	10588	13297	51033	54612	35834
Punjab	2739	3849	1121	1709	3235
Rajasthan	19958	28934	41756	46682	34688
Sikkim	142	108	1065	760	448
Tamil Nadu	33758	33176	56885	63959	55830
Tripura	636	567	1348	983	1665

Name of the State	1993-94 Achievement	1994-95 Achievement	1995-96 Achievement	1996-97 Achievement	1997-98* Achievement
Uttar Pradesh	47722	50908	159073	139801	80958
West Bengal	13389	15526	34278	34722	29490
A & N Islands	21	21	21	78	6
D & N Haveli	60	59	13	50	100
Daman & Diu	13	45	62	92	38
Lakshadweep	0	0	10	105	60
Pondicherry	48	0	36	113	199
TOTAL	372535	390482	863889	806290	641325

*Provisional

Achievements made under PMRY

857. SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA:
SHRI BARJINDER SINGH HAMDARD:

Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item captioned "Banks way behind in meeting Rojgar Yojana Targets" published on 1st March, 1998 in the daily Business Standard;

(b) if so, whether it is a fact that Prime Minister Rozgar Yojana's targets would not be achieved during the last few years; and

(c) if so, what targets were fixed and the achievements made under PMRY during 1995-96, 1996-97 and 1997-98?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS & EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): (a) No, Sir. The Business Standard Limited have reported that they had no publication of Business Standard on Sunday the 1st March, 1998.

(b) and (c) Do not arise.

बिहार में पंचायत समिति, जिला परिषद के चुनाव

858. श्री ईश दत्त यादव: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में अभी तक पंचायत समिति, जिला परिषद् और उनके मुखिया तथा सरपंच के चुनाव न कराये जाने के क्या कारण हैं जबकि उन निकायों के गठन से छह माह की अवधि के भीतर चुनाव कराए जाने अनिवार्य हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्तमान में किसी न्यायालय द्वारा इस संबंध में कोई स्थगन आदेश नहीं दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो वहां ये चुनाव कब तक कराए जाने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रलय के राज्य मंत्री (श्री बाबा गौड़ा पाटिल): (क) से (ग) पटना उच्च न्यायालय ने 1994 की जी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 3351 और सदृश मामलों को बिहार पंचायती राज अधिनियम, 1993 के कतिपय उपबंधों को खारिज करके रिट याचिकाओं का निपटान कर दिया था। उच्च न्यायालय ने पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित उपबंधों को खारिज कर दिया और निर्देश दिया कि यादवों, कोरियों और कुर्मियों जैसे कतिपय वर्गों जिनका राजनीतिक रूप से अच्छा प्रतिनिधित्व है को निकालकर पिछड़े वर्गों की सूची में संशोधन किया जाना चाहिए और समग्र आरक्षण को भी 50% तक सीमित किया जाना चाहिए। पटना उच्च न्यायालय ने पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति के प्रमुख और जिला परिषद के अध्यक्ष के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित बिहार पंचायती राज अधिनियम, 1993 के खण्ड 15(7) में निहित उपबंधों को भी इस आधार पर खारिज कर दिया कि ये एकमात्र पद हैं और इनको आरक्षण देने का अभिप्राय शत-प्रतिशत आरक्षण देना होगा। बिहार सरकार ने एस.एल.पी. सं. 9724-9728, 9819-9825 के जरिए सर्वोच्च न्यायालय में मामला दायर किया। दिनांक 22-07-1997 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया।

"चूंकि भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधन तथा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 की